

प्रेषक,

आर०पी०फुलोरिया,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग देहरादून दिनांक 19 ^{अगस्त} जुलाई, 2009

विषय— वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए विभिन्न अबचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 488/रा०नि०आ०/956-ले०/2008 दिनांक 04 अगस्त 2009 तथा शासनादेश संख्या 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 एवं शासनादेश संख्या: 517/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009, व शासनादेश संख्या 488/XII/09/82(05)/2009 दिनांक 31 जुलाई 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित अबचनबद्ध मदों यथा— मानदेय, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान तथा अन्य व्यय के सापेक्ष कमशः रु० 901 हजार एवं रु० 7511 हजार, इस प्रकार कुल रु० 8412 हजार (रु० चौरासी लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं मानक मदों में नियमानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
2. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि की फॉट, अविलम्ब कर धनराशि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखना सुनिश्चित किया जाय।
3. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्यय 2009-10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो आय-व्यय प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जाय।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम, उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी०एम० 13 पर नियमित रूप से सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।

6. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी बी०एम०-17 पर आवंटन संबंधी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण- वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेश के क्रम में जारी करेंगे। अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। जिसके लिए संबंधित उत्तरदायी होंगे।
 7. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह की स्वीकृति/ व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए तत्संबंधी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनोदशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
 8. प्रत्येक माह विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण- वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी०एम०-17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 9. विभाग में जहाँ केन्द्रीयित क्रय प्रक्रिया लागू है, या दर अनुबन्ध किये जाते हैं, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होते ही एक प्रोक्योरमेन्ट प्लान बना लेंगे। इसी प्रकार पूंजीगत कार्यों का भी एक एक्सन प्लान तैयार कर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
 10. निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/ पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
 11. निर्माण कार्य हेतु पूरे वर्ष की फेजिंग करते हुए लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाय।
 12. जिन योजनाओं में विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो, में विभागाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय ताकि इन के अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।
 13. मित्तव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 14. निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2010 तक करते हुए अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- इस संबंध होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अधीन संलग्न में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष की अबचनबद्ध मदों के अन्तर्गत किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 102 (NP)/XXVII-4/2009 दिनांक 19 अगस्त 2009 में प्राप्त उसकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक गणोपरि

भवदीय,

(आर०पी०फुलोरिया)
संयुक्त सचिव

संख्या: 566 (1)/XII/09 82(05)09तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी-1, /105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
- ✓ 6- एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(जे०एल०शर्मा)
अनु सचिव

तालिका-I

अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य : ग्राम्य विकास कार्यक्रम-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06-राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों आदि हेतु)

क.सं.	मानक मद	अवमुक्त धनराशि (हजार रुपये में)
1	07-मानदेय	17
2.	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	767
2.	42-अन्य व्यय	117
	योग:7	901

(रुपये नौ लाख एक हजार मात्र)

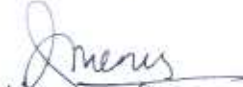
तालिका-II

अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य : ग्राम्य विकास कार्यक्रम-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-07-राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय

क.सं.	मानक मद	अवमुक्त धनराशि (हजार रुपये में)
1	07-मानदेय	463
2.	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	2131
2	42-अन्य व्यय	4917
	योग:-	7511

(रुपये पिच्चतर लाख ग्यारह हजार मात्र)

महायोग:- रू0 84,12,000-00 (रुपये चौरासी लाख बारह हजार मात्र)


(ज०एल०शर्मा)
अनु सचिव।